रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-07042022-234961
CG-DL-E-07042022-234961

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 185] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अप्रैल 7, 2022/चैत्र 17, 1944
No. 185] NEW DELHI, THURSDAY, APRIL 7, 2022/CHAITRA 17, 1944

भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण

अधिसूचना

नई दिल्ली, 7 अप्रैल, 2022

फा. क्र. सी/(5)/2021-एफईए-II.—धारा 11 की उप-धारा (2) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, खंड (बी) के उप-खंड (i) के साथ पठित भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण अधिनियम, 1997 (1997 का 24) की उक्त धारा की उप-धारा (1) के अनुसार, भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण दूरसंचार टैरिफ आदेश, 1999 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित आदेश देता है, अर्थात् :-

दूरसंचार टैरिफ (अड़सठवां संशोधन)

आदेश, 2022

(2022 का 03)

1. संक्षिप्त शीर्षक, विस्तार और प्रारंभ:

(1) इस आदेश को दूरसंचार टैरिफ (अड़सठवां संशोधन) आदेश, 2022 कहा जा सकता है।

(2) यह आदेश राजपत्र में इसके प्रकाशन की तिथि से प्रभावी होगा।

2. दूरसंचार टैरिफ आदेश, 1999 की अनुसूची II में, मद (8) के तहत, उप-मद (8.ए) के लिए, निम्नलिखित उप-मद और उससे संबंधित प्रविष्टि को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्: -

मद	टैरिफ़
"(8.ए) यूएसएसडी-आधारित मोबाइल बैंकिंग और भुगतान सेवाओं के लिए आउटगोइंग यूएसएसडी सत्र के लिए टैरिफ	शून्य"

डॉ. एम.पी. तंगीराला, प्रधान सलाहकार (एफ एंड ईए)

[विज्ञापन-III/4/असा./07/2022-23]

नोट 1 - दूरसंचार टैरिफ आदेश, 1999 भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग III, खंड 4 में अधिसूचना संख्या 99/3 दिनांक 9 मार्च, 1999 के तहत प्रकाशित किया गया था, और बाद में नीचे दिए गए अनुसार संशोधित किया गया था: -

संशोधन क्र.	अधिसूचना संख्या और तिथि
1ला	301-4/99-भादूविप्रा (ईकॉन) दिनांक 30.3.1999
2रा	301-4/99-भादूविप्रा (ईकॉन) दिनांक 31.5.1999
3रा	301-4/99-भादूविप्रा (ईकॉन) दिनांक 31.5.1999
4था	301-4/99-भादूविप्रा (इकॉन) दिनांक 28.7.1999
5वां	301-4/99-भादूविप्रा (इकॉन) दिनांक 17.9.1999
6वां	301-4/99-भादूविप्रा (इकॉन) दिनांक 30.9.1999
7वां	301-8/2000-भादूविप्रा (इकॉन) दिनांक 30.3.2000
8वां	301-8/2000-भादूविप्रा (इकॉन) दिनांक 31.7.2000
9वां	301-8/2000-भादूविप्रा (ईकॉन) दिनांक 28.8.2000
10 वां	306-1/99-भादूविप्रा (इकॉन) दिनांक 9.11.2000
11 वां	310-1(5)/भादूविप्रा-2000 दिनांक 25.1.2001
12 वां	301-9/2000-भादूविप्रा (ईकॉन) दिनांक 25.1.2001
13 वां	303-4/भादूविप्रा-2001 दिनांक 1.5.2001
14 वां	306-2/भादूविप्रा-2001 दिनांक 24.5.2001
15 वां	310-1(5)/भादूविप्रा-2000 दिनांक 20.7.2001
16 वां	310-5(17)/2001-भादूविप्रा (ईकॉन) दिनांक 14.8.2001
17 वां	301/2/2002-भादूविप्रा (ईकॉन) दिनांक 22.1.2002
18 वां	303/3/2002-भादूविप्रा (इकॉन) दिनांक 30.1.2002
19 वां	303/3/2002-भादूविप्रा (इकॉन) दिनांक 28.02.2002
20 वां	312-7/2001-भादूविप्रा (इकॉन) 14.3.2002
21 वां	301-6/2002-भादूविप्रा (इकॉन) दिनांक 13.6.2002
22 वां	312-5/2002-भादूविप्रा (इको) दिनांक 4.7.2002
23 वां	303/8/2002-भादूविप्रा (इकॉन) दिनांक 6.9.2002
24 वां	306-2/2003-इकॉन दिनांक 24.1.2003
25 वां	306-2/2003-इकॉन दिनांक 12.3.2003
26 वां	306-2/2003-इकॉन दिनांक 27.3.2003
27 वां	303/6/2003-भादूविप्रा (इकॉन) दिनांक 25.4.2003
28 वां	301-51/2003-इकॉन दिनांक 5.11.2003

29 वां	301-56/2003-इकॉन दिनांक 3.12.2003
30 वां	301-4/2004(इकॉन) दिनांक 16.1.2004
31 वां	301-2/2004-इको दिनांक 7.7.2004
32 वां	301-37/2004-इको दिनांक 7.10.2004
33 वां	301-31/2004-इको दिनांक 8.12.2004
34 वां	310-3(1)/2003-इको दिनांक 11.3.2005
35 वां	310-3(1)/2003-इको दिनांक 31.3.2005
36 वां	312-7/2003-इको दिनांक 21.4.2005
37 वां	312-7/2003-इको दिनांक 2.5.2005
38 वां	312-7/2003-इको दिनांक 2.6.2005
39 वां	310-3(1)/2003-इको दिनांक 8.9.2005
40 वां	310-3(1)/2003-इको दिनांक 16.9.2005
41 वां	310-3(1)/2003-इको दिनांक 29.11.2005
42 वां	301-34/2005-इको दिनांक 7.3.2006
43 वां	301-2/2006-इको दिनांक 21.3.2006
44 वां	301-34/2006-इको दिनांक 24.01.2007
45 वां	301-18/2007-इको दिनांक 5.6.2007
46 वां	301-36/2007-इको दिनांक 24.01.2008
47 वां	301-14/2008-इको दिनांक 17.3.2008
48 वां	301-31/2007-इको दिनांक 1.9.2008
49 वां	301-25/2009-ईआर दिनांक 20.11.2009
50 वां	301-24/2012-ईआर दिनांक 19.4.2012
51 वां	301-26/2011-ईआर दिनांक 19.4.2012
52 वां	301-41/2012-एफ एंड ईए दिनांक 19.09.2012
53 वां	301-39/2012-एफ एंड ईए दिनांक 1.10.2012
54 वां	301-59/2012-एफ एंड ईए दिनांक 05.11.2012
55 वां	301-10/2012-एफ एंड ईए दिनांक 17.06.2013
56 वां	301-26/2012-ईआर दिनांक 26.11.2013
57 वां	312-2/2013-एफ एंड ईए दिनांक 14.07.2014
58 वां	312-2/2013- एफ एंड ईए दिनांक 01.08.2014
59 वां	310-5 (2)/2013-एफ एंड ईए दिनांक 21.11.2014
60 वां	301-16/2014-एफ एंड ईए दिनांक 09.04.2015
61 वां	301-30/2016-एफ एंड ईए दिनांक 22.11.2016
62 वां	301-30/2016-एफ एंड ईए दिनांक 27.12.2016
63 वां	312-1/2017-एफ एंड ईए दिनांक 16.02.2018
64 वां	301-20/2018-एफ एंड ईए दिनांक 24.09.2018
65 वां	301-03/2020-एफ एंड ईए दिनांक 03.06.2020
66 वां	सी-3/7/(5)/2021-एफईए-1 दिनांक 27.01.2022
67 वां	सी-3/7/(5)/2021-एफईए-1 दिनांक 31.03.2022

नोट 2 - व्याख्यात्मक ज्ञापन दूरसंचार टैरिफ (अड़सठवां संशोधन) आदेश, 2022 के उद्देश्यों और कारणों की व्याख्या करता है।

व्याख्यात्मक ज्ञापन

1. भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (इसके बाद प्राधिकरण के रूप में संदर्भित) को भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण अधिनियम, 1997 (भादूविप्रा अधिनियम) के तहत स्थापित किया गया है। भादूविप्रा अधिनियम की धारा 11 (2) में अन्य बातों के साथ-साथ कहा गया है: "भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम, 1885 (1885 का 13) में किसी बात के होते हुए भी, प्राधिकरण समय-समय पर, आदेश द्वारा, सरकारी राजपत्र में उन दरों को अधिसूचित कर सकता है, जिन पर भारत के भीतर और भारत के बाहर दूरसंचार सेवाएं इस अधिनियम के तहत प्रदान की जाएंगी, जिसमें वे दरें भी शामिल हैं जिन पर संदेश भारत के बाहर किसी भी देश में प्रसारित किए जाएंगे: जिससे प्राधिकरण को विभिन्न दूरसंचार सेवाओं के लिए दरों को अधिसूचित करने का अधिकार मिलता है।

2. इन शक्तियों का प्रयोग करते हुए, प्राधिकरण असंरचित पूरक सेवा डेटा (यूएसएसडी) आधारित मोबाइल बैंकिंग और भुगतान सेवा सहित विभिन्न दूरसंचार सेवाओं के लिए टैरिफ अधिसूचित करता रहा है। यूएसएसडी आधारित मोबाइल बैंकिंग और भुगतान सेवा के लिए टैरिफ को समय-समय पर संशोधित दूरसंचार टैरिफ ऑर्डर 1999 की अनुसूची II की मद (8) के तहत प्राधिकरण द्वारा निर्धारित सीमा टैरिफ के रूप में विनियमित किया गया है। टीटीओ में वर्तमान संशोधन का उद्देश्य यूएसएसडी आधारित मोबाइल बैंकिंग और भुगतान सेवाओं के लिए ढांचे में संशोधन करना है। इस व्याख्यात्मक ज्ञापन का उद्देश्य इस संशोधन को जारी करने के लिए तर्क और कारण प्रदान करना है।

3. दिसंबर, 2011 में, भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (एनपीसीआई) के यूएसएसडी गेटवे के माध्यम से मोबाइल बैंकिंग सेवाओं के लिए दूरसंचार विभाग (डीओटी) द्वारा वित्तीय सेवा विभाग (डीएफएस) को यूएसएसडी कोड *99# आवंटित किया गया था। अप्रैल, 2012 में, भादूविप्रा ने अनिवार्य किया कि प्रत्येक दूरसंचार सेवा प्रदाता (टीएसपी) को यूएसएसडी के मामले में अपने ग्राहकों को बैंकिंग सेवाएं प्रदान करने के लिए बैंकों को यूएसएसडी का उपयोग करने की सुविधा प्रदान करनी चाहिए। नवंबर, 2012 में, एनपीसीआई ने यूएसएसडी चैनल के माध्यम से मोबाइल बैंकिंग को सक्षम करने के लिए यूएसएसडी गेटवे (नेशनल यूनिफाइड यूएसएसडी प्लेटफॉर्म) लॉन्च किया। 2013 में, प्राधिकरण ने मोबाइल बैंकिंग (सेवा की गुणवत्ता) (संशोधन) विनियम, 2013 के माध्यम से मोबाइल बैंकिंग लेनदेन को पूरा करने के लिए चरणों की अधिकतम संख्या दो से बढ़ाकर पांच कर दी।

4. दूरसंचार टैरिफ (छप्पनवां संशोधन) आदेश, 2013 के माध्यम से प्राधिकरण ने, यूएसएसडी आधारित मोबाइल बैंकिंग सेवा के लिए प्रति यूएसएसडी सत्र में रु. 1.50 की सीमा टैरिफ को निर्धारित किया और मोबाइल बैंकिंग सेवाएं प्रदान करने के लिए यूएसएसडी के उपयोग के लिए बैंकों के एजेंटों को एक्सेस सेवा प्रदाताओं के साथ इंटरफेस करने के लिए एक रूपरेखा की स्थापना की। इसके अलावा, वित्तीय समावेशन के लिए यूएसएसडी के माध्यम से मोबाइल बैंकिंग की सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से, प्राधिकरण ने दूरसंचार टैरिफ (इकसठवां संशोधन) आदेश, 2016 के माध्यम से बैंकिंग और भुगतान सेवाओं के लिए यूएसएसडी-आधारित उच्चतम सीमा टैरिफ को रु. 1.50 से घटाकर रु. 0.50 प्रति सत्र कर दिया और मोबाइल बैंकिंग (सेवा की गुणवत्ता) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2016 के माध्यम से प्रत्येक यूएसएसडी सत्र में चरणों की संख्या पांच से बढ़ाकर आठ चरणों में की गई। प्राधिकरण ने इस सेवा के उपयोग और लोकप्रियता को बढ़ाने के लिए एनपीसीआई/बैंकों को सभी भुगतान प्लेटफार्मों पर लेनदेन का समर्थन करने के लिए सॉफ्टवेयर सुविधाओं में सुधार, उपयोगकर्ता के अनुकूल मेनू का डिजाइन, उपभोक्ता जागरूकता में वृद्धि, एकीकृत यूएसएसडी प्लेटफॉर्म विकसित करने जैसे विभिन्न तंत्रों का भी सुझाव दिया।

5. इसके बाद, भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने भुगतान के डिजिटलीकरण को प्रोत्साहित करने और डिजिटलीकरण के माध्यम से वित्तीय समावेशन को बढ़ाने के उद्देश्य से डिजिटल भुगतान (सीडीडीपी) को गहरा करने पर एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया। समिति ने इसे अपनाने और लोकप्रियता बढ़ाने के लिए यूएसएसडी शुल्कों को और युक्तिसंगत बनाने की सिफारिश की। आरबीआई ने प्राधिकरण से सीडीडीपी द्वारा की गई सिफारिशों पर अनुवर्ती कार्रवाई करने और इसके लिए आवश्यक नियामक ढांचा प्रदान करने का आग्रह किया।

6. वित्तीय सेवा विभाग (डीएफएस), भारत सरकार ने भी उच्च-स्तरीय समिति द्वारा की गई सिफारिशों का समर्थन किया और आम लोगों द्वारा विशेष रूप से ग्रामीण / कठिन क्षेत्रों, आबादी के वर्ग में इस सेवा को तेजी से अपनाने की सुविधा के लिए यूएसएसडी टैरिफ माफ करने का अनुरोध किया। जिनके लिए वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री जन धन योजना (पीएमजेडीवाई) खाता योजना की स्थापना की गई है। इस संबंध में डीएफएस के अनुरोध के बाद, प्राधिकरण ने यूएसएसडी शुल्कों को और अधिक युक्तिसंगत बनाने के लिए परामर्श प्रक्रिया शुरू की।

7. तदनुसार, प्राधिकरण ने 24 नवंबर, 2021 को दूरसंचार टैरिफ(66वां संशोधन) आदेश, 2021 पर मसौदा जारी किया, जिसमें मोबाइल बैंकिंग और भुगतान सेवा के लिए प्रति यूएसएसडी सत्र "शून्य" टैरिफ का प्रस्ताव किया गया था। मसौदे के आदेश पर

हितधारकों से टिप्पणियां और प्रति टिप्पणियां क्रमशः 8 दिसंबर, 2021 और 17 दिसंबर, 2021 तक मांगी गई थीं। प्रत्युत्तर में, एक संघ, चार सेवा प्रदाताओं और एक संगठन ने अपनी टिप्पणियाँ प्रस्तुत की और एक संगठन ने अपनी प्रति-टिप्पणी प्रस्तुत की।

8. कुछ हितधारकों ने तर्क दिया है कि चूंकि यूएसएसडी लेनदेन उनके नेटवर्क और बुनियादी ढांचे का उपयोग करते हैं, वे इस सेवा को प्रदान करने में पूंजीगत व्यय के साथ-साथ परिचालन व्यय भी लागू करते हैं। उन्होंने आगे तर्क दिया कि यदि यह सेवा मुफ्त की जाती है, तो उन्हें एनपीसीआई के माध्यम से बैंकों द्वारा इस खर्च के लिए पर्याप्त रूप से मुआवजा दिया जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त, कुछ हितधारकों ने सुझाव दिया कि यदि यूएसएसडी टैरिफ हटा दिए जाते हैं तो इस सेवा से संबंधित विनियामक दायित्वों को भी समाप्त कर दिया जाना चाहिए।

9. एक हितधारक ने यह भी सुझाव दिया कि यूएसएसडी के लिए टैरिफ को चरणबद्ध तरीके से कम किया जाना चाहिए ताकि संशोधित मूल्य निर्धारण और यूएसएसडी सेवाओं के उठाव के बीच किसी भी प्रत्यक्ष संबंध का पता लगाया जा सके।

10. कुछ हितधारकों ने डिजिटल वित्तीय समावेशन में सहायता के लिए टैरिफ हटाने का समर्थन किया है।

11. यूएसएसडी शुल्कों को अन्य सेवाओं के अनुरूप लाने के लिए उन्हें युक्तिसंगत बनाने के लिए, टीएसपी द्वारा दी जा रही प्रमुख सेवाओं के लिए टैरिफ के वर्तमान स्तर की जांच की गई। सितंबर, 2021 को समाप्त तिमाही के लिए वायरलेस सेवा के लिए टैरिफ का वर्तमान स्तर नीचे दी गई तालिका में दर्शाया गया है:

तालिका: सितंबर, 2021 को समाप्त तिमाही के लिए वायरलेस सेवा का औसत टैरिफ

मद	वायरलेस सेवा के लिए मूल्य
आउटगोइंग वॉयस कॉल के लिए औसत टैरिफ (औसत आउटगो प्रति आउटगोइंग मिनट)	रु. 0.04 प्रति मिनट
आउटगोइंग एसएमएस संदेश के लिए औसत टैरिफ	रु. 0.01 प्रति एसएमएस
नोट: उपरोक्त आंकड़े टीएसपी द्वारा प्राधिकरण को प्रस्तुत किए गए आंकड़ों पर आधारित हैं	

12. उपरोक्त तालिका स्पष्ट रूप से इंगित करती है कि मोबाइल बैंकिंग के लिए प्रत्येक यूएसएसडी सत्र के लिए रु. 0.50 की वर्तमान उच्चतम सीमा टैरिफ आउटगोइंग वॉयस कॉल के एक मिनट के औसत टैरिफ के साथ-साथ एक आउटगोइंग एसएमएस की तुलना में काफी अधिक है।

13. साथ ही, राजस्व के मामले में, यूएसएसडी मोबाइल बैंकिंग सत्रों के माध्यम से उत्पन्न कुल राजस्व, उद्योग के कुल राजस्व का लगभग 0.00007% है।

14. यह भी ध्यान देने योग्य है कि इस सेवा को प्रदान करने वाले टीएसपी द्वारा वित्त वर्ष 2021-22 की लगातार दो तिमाहियों के लिए प्रस्तुत की गई जानकारी इंगित करती है कि सेल्फ-केयर सेवा के लिए यूएसएसडी सत्र[1]कुल यूएसएसडी सत्रों का 99.5% हिस्सा है और 0.5% का शेष न्यूनतम हिस्सा, मोबाइल बैंकिंग और भुगतान सेवाओं के लिए यूएसएसडी सत्रों से संबंधित है।

15. यह मान लेना तर्कसंगत है कि यूएसएसडी सेल्फ-केयर सेवा सत्र को संभालने में शामिल नेटवर्क लागत यूएसएसडी मोबाइल बैंकिंग और भुगतान सत्र की लागत के समान है। फिर भी ये सेल्फ-केयर यूएसएसडी सत्र अंतिम-उपयोगकर्ताओं के लिए बिना किसी टैरिफ के उपलब्ध हैं जबकि यूएसएसडी मोबाइल बैंकिंग और भुगतान सेवाओं पर अधिकतम टैरिफ लगाया जा रहा है।

16. इसके अलावा, एक ऑपरेटर वर्तमान में यूएसएसडी गैर- सेल्फ-केयर सेवा को नि:शुल्क प्रदान कर रहा है, जबकि अन्य ऑपरेटर 0.50 रुपये प्रति सत्र के उच्चतम दर पर टैरिफ ले रहे हैं। उपलब्ध जानकारी के विश्लेषण पर, यह देखा गया है कि टैरिफ नहीं लेने वाले ऑपरेटर के लिए यूएसएसडी मोबाइल बैंकिंग और भुगतान सत्रों की संख्या, अधिकतम टैरिफ पर शुरू किए गए सत्रों की संख्या का चार गुना है। इस प्रकार, यह माना जा सकता है कि उपयोगकर्ता उस ऑपरेटर को प्राथमिकता देते हैं जो इस सेवा को निःशुल्क प्रदान करता है। यह प्राधिकरण के विश्लेषण की पुष्टि करता है कि इस सेवा के लिए टैरिफ में कमी आने से इस सेवा को लोकप्रिय बनाने और इसे और अपनाने में मदद मिल सकती है।

---

[1] यूएसएसडी आधारित स्व-देखभाल सेवा से तात्पर्य दूरसंचार सेवा प्रदाताओं द्वारा यूएसएसडी के उपयोग के माध्यम से अपने ग्राहकों को दी जाने वाली सेल्फ-केयर/सेल्फ-हेल्प /सेल्फ-सपोर्ट सेवाओं से है। इस सेवा का उपयोग यूएसएसडी ग्राहकों द्वारा यूएसएसडी कोड डायल करके प्रीपेड बैलेंस, वैधता अवधि, टैरिफ योजना के विवरण आदि के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए किया जाता है।

17. प्राधिकरण का विचार है कि चूंकि यूएसएसडी लक्षित उपयोगकर्ता आम तौर पर कम आय वाली ग्रामीण आबादी हैं जो अभी भी फीचर फोन का उपयोग कर रहे हैं, यूएसएसडी सेवा के लिए कोई टैरिफ नहीं लगाने से यूएसएसडी लेनदेन की संख्या पर सकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है, जो डिजिटल वित्तीय समावेशन प्राप्त करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम होगा। यह उद्योग के राजस्व को भी ज़्यादा प्रभावित नहीं करेगा, विशेष रूप से तब जब सेवा प्रदाताओं द्वारा सेल्फ-केयर सेवाओं के लिए समान लेनदेन निःशुल्क प्रदान किए जा रहे हों। इसलिए, प्राधिकरण ने शेष पहलुओं को अपरिवर्तित रखते हुए मोबाइल बैंकिंग और भुगतान सेवा के लिए यूएसएसडी के लिए निर्धारित टैरिफ को समाप्त करने का निर्णय लिया है। प्राधिकरण सेवा की प्रगति पर नजर रखना जारी रखेगा और दो साल की अवधि के बाद प्रभार की समीक्षा कर सकता है।

TELECOM REGULATORY AUTHORITY OF INDIA

NOTIFICATION

New Delhi, the 7th April, 2022

F. No. C/(5)/2021-FEA-II.—In exercise of the powers conferred upon it under sub-section (2) of section 11, read with sub-clause (i) of clause (b) of sub-section (1) of the said section, of the Telecom Regulatory Authority of India Act, 1997 (24 of 1997), the Telecom Regulatory Authority of India hereby makes the following Order further to amend the Telecommunication Tariff Order, 1999, namely:-

THE TELECOMMUNICATION TARIFF (SIXTY EIGHTH AMENDMENT) ORDER, 2022

(No. 3 of 2022)

1. Short title, extent and commencement:

(1) This Order may be called the Telecommunication Tariff (Sixty Eighth Amendment) Order, 2022.

(2) It shall come into force from the date of its publication in the Official Gazette.

2. In Schedule II to the Telecommunication Tariff Order, 1999, under item (8), for sub-item (8.a), the following sub-item and entry relating thereto shall be substituted, namely: -

ITEM	TARIFF
"(8.a) Charge for outgoing USSD session for USSD-based mobile banking and payment services	Nil"

Dr. M.P. TANGIRALA, Pr. Advisor (F&EA)

[ADVT.-III/4/Exty./07/2022-23]

Note 1 – The Telecommunication Tariff Order, 1999 was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part III, Section 4 under notification No. 99/3 dated 9th March, 1999, and subsequently amended as given below: -

Amendment No.	Notification No. and Date
1st	301-4/99-TRAI (Econ) dated 30.03.1999
2nd	301-4/99-TRAI(Econ) dated 31.05.1999
3rd	301-4/99-TRAI(Econ) dated 31.05.1999
4th	301-4/99-TRAI(Econ) dated 28.07.1999
5th	301-4/99-TRAI(Econ) dated 17.09.1999
6th	301-4/99-TRAI(Econ) dated 30.09.1999
7th	301-8/2000-TRAI(Econ) dated 30.03.2000
8th	301-8/2000-TRAI(Econ) dated 31.07.2000
9th	301-8/2000-TRAI(Econ) dated 28.08.2000
10th	306-1/99-TRAI(Econ) dated 09.11.2000
11th	310-1(5)/TRAI-2000 dated 25.01.2001
12th	301-9/2000-TRAI(Econ) dated 25.01.2001
13th	303-4/TRAI-2001 dated 01.05.2001

14th	306-2/TRAI-2001 dated 24.05.2001
15th	310-1(5)/TRAI-2000 dated 20.07.2001
16th	310-5(17)/2001-TRAI(Econ)dated 14.08.2001
17th	301/2/2002-TRAI(Econ) dated 22.01.2002
18th	303/3/2002-TRAI(Econ) dated 30.01.2002
19th	303/3/2002-TRAI(Econ) dated 28.02.2002
20th	312-7/2001-TRAI(Econ) 14.03.2002
21st	301-6/2002-TRAI(Econ) dated 13.06.2002
22nd	312-5/2002-TRAI(Eco) dated 04.07.2002
23rd	303/8/2002-TRAI(Econ) dated 06.09.2002
24th	306-2/2003-Econ dated 24.01.2003
25th	306-2/2003-Econ dated 12.03.2003
26th	306-2/2003-Econ dated 27.03.2003
27th	303/6/2003-TRAI(Econ) dated 25.04.2003
28th	301-51/2003-Econ dated 05.11.2003
29th	301-56/2003-Econ dated 03.12.2003
30th	301-4/2004(Econ) dated 16.01.2004
31st	301-2/2004-Eco dated 07.07.2004
32nd	301-37/2004-Eco dated 07.10.2004
33rd	301-31/2004-Eco dated 08.12.2004
34th	310-3(1)/2003-Eco dated 11.03.2005
35th	310-3(1)/2003-Eco dated 31.03.2005
36th	312-7/2003-Eco dated 21.04.2005
37th	312-7/2003-Eco dated 02.05.2005
38th	312-7/2003-Eco dated 02.06.2005
39th	310-3(1)/2003-Eco dated 08.09.2005
40th	310-3(1)/2003-Eco dated 16.09.2005
41st	310-3(1)/2003-Eco dated 29.11.2005
42nd	301-34/2005-Eco dated 07.03.2006
43rd	301-2/2006-Eco dated 21.03.2006
44th	301-34/2006-Eco dated 24.01.2007
45th	301-18/2007-Eco dated 05.06.2007
46th	301-36/2007-Eco dated 24.01.2008
47th	301-14/2008-Eco dated 17.03.2008
48th	301-31/2007-Eco dated 01.09.2008
49th	301-25/2009-ER dated 20.11.2009
50th	301-24/2012-ER dated 19.04.2012
51st	301-26/2011-ER dated 19.04.2012
52nd	301-41/2012-F&EA dated 19.09.2012
53rd	301-39/2012-F&EA dated 01.10.2012
54th	301-59/2012-F&EA dated 05.11.2012
55th	301-10/2012-F&EA dated 17.06.2013
56th	301-26/2012-ER dated 26.11.2013

57th	312-2/2013-F&EA dated 14.07.2014
58th	312-2/2013-F&EA dated 01.08.2014
59th	310-5 (2)/2013-F&EA dated 21.11.2014
60th	301-16/2014-F&EA dated 09.04.2015
61st	301-30/2016-F&EA dated 22.11.2016
62nd	301-30/2016-F&EA dated 27.12.2016
63rd	312-1/2017-F&EA dated 16.02.2018
64th	301-20/2018-F&EA dated 24.09.2018
65th	301-03/2020-F&EA dated 03.06.2020
66th	C-3/7/(5)/2021-FEA-1 dated 27.01.2022
67th	C-3/7/(5)/2021-FEA-1 dated 31.03.2022

Note 2 – The Explanatory Memorandum explains the objects and reasons for the Telecommunication Tariff (Sixty Eighth Amendment) Order, 2022.

EXPLANATORY MEMORANDUM

1. The Telecom Regulatory Authority of India (hereinafter referred to as the Authority) is established under the Telecom Regulatory Authority of India Act, 1997 (TRAI Act). Section 11(2) of the TRAI Act *inter alia* states: *"Notwithstanding anything contained in the Indian Telegraph Act, 1885 (13 of 1885), the Authority may, from time to time, by order, notify in the Official Gazette the rates at which the telecommunication services within India and outside India shall be provided under this Act including the rates at which messages shall be transmitted to any country outside India"* thereby empowering the Authority to notify rates for various telecommunication services.

2. In exercise of these powers, the Authority has been notifying tariffs for various telecommunication services including Unstructured Supplementary Service Data (USSD) based mobile banking and payment service. The tariffs for USSD based mobile banking and payment service have been regulated in the form of ceiling tariffs prescribed by the Authority under item (8) of Schedule II of the Telecommunication Tariff Order 1999, as amended from time to time. The purpose of the present amendment to the TTO is to revise the framework for USSD based mobile banking and payment services. This explanatory memorandum aims to provide the rationale and reasons for issuing this amendment.

3. In December, 2011, Department of Financial Services (DFS) was allocated USSD code *99# by the Department of Telecommunication (DoT) for mobile banking services through the USSD gateway of National Payment Corporation of India (NPCI). In April, 2012, TRAI mandated that every Telecom Service Provider (TSP) should facilitate the banks to use USSD to provide banking services to its customers in not more than two stage entry of options in the case of USSD. In November, 2012, NPCI launched a USSD Gateway (National Unified USSD Platform) for enabling mobile banking through the USSD channel. In 2013, the Authority through the Mobile Banking (Quality of Service) (Amendment) Regulations, 2013, increased the maximum number of stages for completing a mobile banking transaction from two to five, primarily to increase the number of banking services available to USSD consumers.

4. The Authority through Telecommunication Tariff (Fifty Sixth Amendment) Order, 2013, prescribed a ceiling tariff of Rs. 1.50 per USSD session for USSD-based mobile banking service and established a framework to facilitate the agents of the banks to interface with the access service providers for use of USSD to provide mobile banking services. Further, with a view to facilitate mobile banking through USSD for financial inclusion, the Authority reduced the USSD- based ceiling tariff for banking and payment services from Rs. 1.50 to Rs. 0.50 per session through the Telecommunication Tariff (Sixty First Amendment) Order, 2016 and increased the number of stages from five to eight stages per USSD session through the Mobile Banking (Quality of Service) (Second Amendment) Regulations, 2016. The Authority also suggested various mechanisms viz., improvement in software features, design of user-friendly menu, increase in consumer awareness, developing Unified USSD platform to support transactions across all payment platforms to the NPCI/Banks to increase usage and popularity of this service.

5. Subsequently, the Reserve Bank of India (RBI) constituted a High-Level Committee on Deepening of Digital Payments (CDDP) with the objective of encouraging digitization of payments and enhancing financial inclusion through digitization. The committee recommended further rationalization of USSD charges to increase its adoption and popularity. RBI urged the Authority for a follow-up action on the recommendations made by CDDP and provide the required regulatory framework for the same.

6. Government of India, Department of Financial Services (DFS) also supported the recommendations made by the High-Level Committee and requested for waiving off USSD charges to facilitate faster adoption of this service by common people especially in rural/ difficult areas, the segment of population for whom the Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana (PMJDY) Accounts scheme has been established to promote financial inclusion. Following a request from the DFS in this regard, the Authority initiated a consultation process to further rationalize USSD charges.

7. Accordingly, the Authority issued draft Telecommunication Tariff (66th Amendment) Order, 2021 on 24th November, 2021 proposing "Nil" charges per USSD session for mobile banking and payment service. The comments and counter comments on the draft Order were sought from the stakeholders by 8th December, 2021 and 17th December, 2021 respectively. In response, one association, four service providers and one organization furnished their comments and one organization submitted its counter comment.

8. Some stakeholders have contended that since USSD transactions make use of their network and infrastructure, they incur capex investment as well as operational expenditure in providing this service. They further argued that in case this service is made free of cost, they must be adequately compensated for this expenditure by banks through NPCI. Additionally, a few stakeholders suggested that in case USSD charges are removed then the regulatory obligations related to this service should also be done away with.

9. One stakeholder also suggested that the charges for USSD should be brought down in a phased manner to ascertain any direct correlation between the revised pricing and uptake of the USSD services.

10. Some stakeholders have favored the removal of charge to aid digital financial inclusion.

11. In order to rationalize USSD charges to bring them in line with other services, the present level of tariffs for the major services being offered by the TSPs was examined. The present level of tariffs for wireless service for the quarter ended September, 2021 is indicated in the Table below:

Table: Average tariffs for wireless service for the quarter ended September, 2021

Item	Value for wireless service
Average tariff for outgoing voice call (Average outgo per outgoing minute)	Re. 0.04 per minute
Average tariff for outgoing SMS message	Re. 0.01 per SMS
Note: The above figures are based on data submitted by the TSPs to the Authority	

12. The above table clearly indicates that the present ceiling tariff of Rs. 0.50 for each USSD session for mobile banking is quite high as compared to the average tariff for one minute of outgoing voice call as well as for one outgoing SMS.

13. Also, in terms of revenue, the total revenue generated through USSD mobile banking sessions is quite small at approximately 0.00007% of the total revenue of the industry.

14. It is also pertinent to note that the information furnished for two consecutive quarters of F.Y 2021-22 by the TSPs providing this service indicates that the USSD sessions for self-care service[2] constitute 99.5% of the total USSD sessions and the remaining miniscule share of 0.5% pertains to USSD sessions for mobile banking and payment services.

15. It is logical to assume that the network cost involved in handling USSD self-care service session is the same as the cost for USSD mobile banking and payment session. Still these self-care USSD sessions are available without any charge to the end-users whereas USSD mobile banking and payment services are being charged at the ceiling tariff.

16. Further, one operator is providing USSD non-self-care service free of charge at present whereas, other operators are charging at the ceiling tariff of Rs. 0.50 per session. On analysis of the information available, it is observed that the number of USSD mobile banking and payment sessions, for the operator that doesn't charge, is four times the number of sessions initiated at ceiling tariff. Thus, it can be assumed that the users prefer the operator providing this service free of charge. This substantiates the analysis of the Authority that a reduction in charge for this service may help popularize this service and increase its adoption.

[2] USSD based self-care service refers to the self-care/ self-help/ self-support services offered by the telecom service providers to their subscribers through the use of USSD. This service is used by USSD subscribers to seek information on pre-paid balance, validity period, details of tariff plan etc. by dialing a USSD code.

17. The Authority is of the view that since the USSD target users are generally low-income rural population who are still using feature phones, imposing no charge for USSD service can have a positive impact on number of USSD transactions, which will be a significant step towards achieving digital financial inclusion. It will also not impact the revenues of the industry substantially, especially when similar transactions for self-care services are being provided free by the service providers. Therefore, the Authority has decided to do away with the charges prescribed for USSD for mobile banking and payment service, while keeping the remaining aspects unchanged. The Authority will continue to keep a watch on the progress of service and may review the charge after a period of two years.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. MANOJ KUMAR VERMA